आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 28.11.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने और डिग्रियां तथा प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए।
- प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वन भूमि का मामला सुलझा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
- केंद्र सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चंपावत जिले ने लगातार चौथे महीने पहला स्थान प्राप्त किया।
- देहरादून जिला प्रशासन का सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और उपाधियां तथा प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इसमें देरी से विद्यार्थियों को अवसरों का नुकसान होता है। उन्हें उपयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण रोज़गार पाने में बाधा आती है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा देने, करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। यह भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

रेखा आर्या

प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय शुरू करने को लेकर लगातार बाधा बन रहे वन भूमि का मामला सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब 2026 के शैक्षणिक सत्र से इसके शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
खेल मंत्री ने बताया कि चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में भी अगले साल से कक्षाएं शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

झरने जमे

उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में तापमान कम होने के कारण नदी और सहायक नदियों के झरने पूरी तरह जम चुके हैं। ये सब वन विभाग के ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क में अवैध शिकार रोकने और पार्क क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीवों की गतिविधियों की जानकारी के लिए गोमुख सहित केदारताल ट्रैक और नेलांग घाटी में करीब पचास ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वहीं शीतकाल में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवैध शिकार रोकने और पार्क क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीवों की गतिविधियों की जानकारी के लिए गोमुख सहित केदारताल ट्रैक और नेलांग घाटी में करीब पचास ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। पार्क के रेंजर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि गंगोत्री धाम में इन दिनों तापमान जीरो डिग्री से नीचे जा रहा है। इसलिए गंगोत्री धाम सहित नेलांग घाटी और गोमुख ट्रैक पर सभी नदी नाले जम गए हैं। पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए पाले से ढकी बर्फ को आग में पिघलाकर प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके साथ ही इन विषम परिस्थितियों में विभागीय कर्मचारियों ने समुद्रतल से करीब 10 से 13 हजार फीट की ऊंचाई वाले स्थानों पर करीब पचास ट्रैप कैमरे लगाए हैं। जिनसे शीतकाल और बर्फबारी के दौरान वन्यजीवों के अवैध शिकार की घटनाओं पर नजर रखी जाती है। साथ ही दुर्लभ वन्यजीवों स्नो लेपर्ड, भरल, भूरा भालू और कस्तूरी मृग आदि की गतिविधियों और जनसंख्या की गिनती होती है।

बीस सूत्रीय पहला स्थान

चंपावत जिले ने केंद्र सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगातार चौथे महीने पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले ने पारदर्शी प्रशासन, परिणाम आधारित कार्यप्रणाली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य स्तर पर यह सर्वोच्च स्थान हासिल किया। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी दीप्तकीर्ति तिवारी ने बताया कि चम्पावत ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर माह की रैंकिंग में भी अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। उत्तराखंड शासन के अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग की ओर से जारी प्रतिवेदन के अनुसार, चम्पावत को कुल 129 अंकों में से 122 अंक प्राप्त हुए, जो 94 दशमलव 5–7 प्रतिशत सफलता दर को दर्शाता है। इस रैंकिंग में बागेश्वर जिला दूसरे और ऊधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर रहा। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल शीर्ष स्थान प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे।

अतिक्रमण

देहरादून जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने पछुवादून क्षेत्र में शक्ति नगर किनारे ऊर्जा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया। इस भूमि पर कई परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा था और मजारें बनाई थी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश भर में दो करोड़ से ज़्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट–

सांसद बैठक

नैनीताल–ऊधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी काठगोदाम में अपने संसदीय क्षेत्र की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को तय सीमा पर परियोजना के निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

कार्य□ाला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की सचिव पायल सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013" पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों, रोकथाम संबंधी उपायों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। सचिव ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक व संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को यह संदेश दिया गया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है और इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाना महिलाओं का वैधानिक अधिकार है।